"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2016—माघ 23, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्रमांक ई 7-22/2004/1/2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 19 (1) के प्रावधान अनुसार श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. को विभागीय आदेश दिनांक 27-10-2015 द्वारा दिनांक 06-11-2015 से 20-11-2015 (15 दिवस) तक स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 09-11-2015 से 16-11-2015 तक (08 दिवस) की अवधि को लघुकृत अवकाश में परिवर्तित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2016

क्रमांक 171/933/2013/16.—''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 4'' एवं सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 10 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा ''राज्य सलाहकार समिति'' का निम्नानुसार गठन करती है :—

क्र. (1)	पद का नाम (2)		धारित व्यक्ति अथवा पद का नाम (3)
1.	अध्यक्ष	—	श्रम मंत्री
2.	राज्य विधान सभा के दो सदस्य	1	श्रीमती चंपादेवी पावले, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया
		2	श्री नवीन मारकण्डेय, आरंग, जिला-रायपुर
3.	पदेन सचिव	—	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम
4.	पदेन सदस्य	—	मुख्य निरीक्षक/श्रमायुक्त
5.	पदेन सदस्य	—	मुख्य कारखाना निरीक्षक
6.	भवन कर्मकार प्रतिनिधि सदस्य	1	श्री श्याम लाल साहू, रायपुर
		2	श्री गणेश राम निर्मलकर, कुर्रा, अभनपुर
		3	श्रीमती प्रमिला देवांगन, भारतीय मजदूर संघ कार्यालय हनुमान मंदिर के पास, उद्यान मार्ग, चौबे कॉलोनी, रायपुर.
7.	भवन कर्मकार नियोजक प्रतिनिधि सदस्य	1	डॉ. निमाई विश्वास, माना, रायपुर
		2	श्री कोमल सिंह ठाकुर, ग्राम-मुढ़ीपार, हिर्री माईन्स, जिला-बिलासपुर.
8.	गृह निर्माण मंडल के इन्जीनियर सदस्य	—	श्री हेमंत वर्मा, कार्यपालन अभियंता, गृह निर्माण मण्डल, नया रायपुर परियोजना संभाग क्रमांक-1, रायपुर.
9.	निर्माण क्षेत्र से जुड़ा इंजीनियर	—	श्री मनोज पराशर, प्लाट नंबर-857, 858, मुख्य डाकघर के पास, कोरबा.
10.	वास्तुविद-सदस्य	—	श्री चंद्रशेखर राठौर, एच.आई.जी.-2, क्वा. नं.-3, सेक्टर-3 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, डंगनिया, रायपुर.
11.	सदस्य	—	भारतीय जीवन बीमा निगम के महाप्रबंधक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 20-31/2015/ग्यारह/(छै).— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत् अधिसूचित ''ब्याज अनुदान योजना'' को क्रियान्वित करने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04-06-2015 द्वारा जारी ''छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम-2014'' में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा-7 के उप पैरा-3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

7.3 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण ''उपाबंध 3'' के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यमों, फिल्म उद्योगों के विकास एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों, मध्यम तथा वृहद उद्योगों, मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में प्रबंधक/सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से स्थल निरीक्षण व परीक्षण करवाकर स्वत्वों के नियमों के अनुसार होने पर ''उपाबंध 4'' में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा.

किसी भी औद्योगिक इकाई/सेवा उद्यम के समस्त स्वत्वों का स्थल निरीक्षण/परीक्षण यथासंभव उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया जावेगा जिनके द्वारा प्रथम प्रकरण में स्थल निरीक्षण/परीक्षण किया गया था.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा-9 के उप पैरा-1 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

9.1 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी. उद्योग आयुक्त/संचालक के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य शासन को की जा सकेगी.

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा-9 के उप पैरा-2 का लोप किया जाये.

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 20-87/2012/ग्यारह/(छै).— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-10-2012 द्वारा जारी ''कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012'' में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के पैरा-6 कार्य नीति के उप पैरा-3 का लोप किया जाये.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा-7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

7 **छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन :—** इसके अंतर्गत निम्नानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य बजट, मण्डी निधि आदि स्रोतों से किया जायेगा :—

i खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण

ii कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास (उद्यानिकी और गैर उद्यानिकी क्षेत्र में)

iii ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना

iv रीफर वाहन योजना

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 20-109/2009/ग्यारह/(छै).— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2009-14 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान छूट एवं रियायतें के तहत् अधिसूचित "ब्याज अनुदान योजना" को क्रियान्वित करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-10-2010 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम-2009" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना में पैरा-7 के उप पैरा-3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

7.3 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण "उपाबंध 5" के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में सहायक प्रबंधक/प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन व परीक्षण करवाकर स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में "उपाबंध 8" में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा.

(दो) उक्त अधिसूचना में पैरा-9 के उप पैरा-1 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

9.1 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी. उद्योग आयुक्त/संचालक के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य शासन को की जा सकेगी.

(तीन) उक्त अधिसूचना में पैरा-9 के उप पैरा-2 का लोप किया जाये.

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक-M.P./3216 को दिनांक 19-12-2015 से 18-06-2016 एवं बॉयलर क्रमांक सी.जी./489 (मेकर क्र. 358) को दिनांक 12-12-2015 से 11-01-2016 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 3-4/2013/38-2.— छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 688/निवि/एस. एण्ड ओ./2013/5479, दिनांक 27-11-2015 द्वारा कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, पलौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर के अध्यादेश क्रमांक 58 से 63 का अनुमोदन छ.ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम की धारा 29 के तहत् किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

3. उपरोक्त आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

No. F 3-4/2013/38-2.— Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Lettar No. 688/S & O/2013/5479, Dated 27-11-2015 has approved the Ordinances No. 58 to 63 of Kalinga University, Village-Kotni, Palod, Tahsil-Arang, Distt.-Raipur under Section 29 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.

3. The above Ordinances shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, संयुक्त सचिव.

ORDINANCE 58

Bachelor of Commerce (B. COM.)

1. Introduction: Bachelor of Commerce (B.Com.) is a three year undergraduate degree program which provides a foundation in all aspects of commerce, so as to train candidates to handle positions of responsibility in the fields of accounting and business management. As this course is directly related to the basic business requirements, the prospect of this course is very bright and it is the most studied program all over the world. It covers a very wide realm of employment prospects globally.

2. Title: Bachelor of Commerce (B. Com.)

3. Faculty: Faculty of Commerce

4. Duration: Three years

5. Eligibility: 10+2 Passed.

6. Seats: The basic unit will be that of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up.

7. Admission Procedure: As Specified in the Ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed.

8. Academic Year: The academic session will start in July every year and will continue till June next.

9. Selection Procedure: The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every academic cycle.

The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the university.

The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark Sheets or 10+ 2 passing certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected on any one of the following ground:

1. The fee is not paid.
2. The application form is not signed by candidate and his or her parent / guardian, wherever required.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11. Course structure: There shall be 6 Theory Papers in 1st year, 6 in 2nd year, and 6 in 3rd year, all papers bearing 100 marks. In the final year the students get to choose any one specialization out of the following combinations.

(i)	Paper V	Financial Management
	Paper VI	Management Accounting
(ii)	Paper V	Principles of Marketing
	Paper VI	International Marketing
(iii)	Paper V	Fundamentals of Insurance
	Paper VI	Indian Banking System
(iv)	Paper V	Internet & World Wide Web
	Paper VI	Essentials of E-Commerce
(v)	Paper V	Human Resource Management
	Paper VI	Industrial Relations

12. Eligibility to Pass: A student requires to obtain 40% Marks in each paper, in theory and practical Examination separately and 45% marks in aggregate to pass the Semester End/ Year End Examination.

13. Evaluation and : Examination — Refer to Ordinance 51(8) of the First Ordinances of Kalinga University.

14. Eligibility criteria for : ATKT — Refer to Ordinance 51(10) of the First Ordinances of Kalinga University.

15. General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university, based on the recommendation of the Board of Studies of the subject, shall be final, Provided that a prior approval for the change from Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) shall be necessary. Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.

ORDINANCE 59

Bachelor of Commerce-Honors (B.COM.-Honors)

1. Introduction: B.Com (Hons) is a three year undergraduate degree program modeled to provide the student with a wide range of managerial skills and building competence in a particular area. It also helps in preparing the students for the realities of the modern business world. This program acts as a stepping stone for the students who wish to continue with higher education and pursue research in their chosen field as well as more advanced coursework. With the help of this course, students get specialization in a particular subject in a final year.

   This program is basically designed to integrate knowledge and skill and provide a high quality education in business studies. It is an intensive program which assists to serve the needs of those who intend to work in the business houses and also start their own businesses.

2. Title: Bachelor of Commerce-Honors (B.Com.-Honors)

3. Faculty: Faculty of Commerce

4. Duration: Three years

5. Eligibility: 10+2 Passed.

6. Seats: The basic unit will be that of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up.

7. Admission Procedure: As Specified in the Ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed.

8. Academic Year: The academic session will start in July every year and will continue till June next.

9. Selection Procedure: The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every academic cycle.

The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the university.

The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark Sheets or 10+ 2 passing certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected on any one of the following ground:

1. The fee is not paid.

2. The application form is not signed by candidate and his or her parent / guardian, wherever required.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11. Course structure: There shall be 6 Theory Papers in 1st year, 7 in 2nd year, and 6 Papers in 3rd year, one paper in 1st year 100 marks and all other papers bearing 125 marks In addition, there shall be one Viva-Voce exam in 3rd year carrying 50 marks. In the final year the students get to choose one particular area of specialization and get special expertise in that area by appearing in two papers.

The student can choose any one elective group out of :

i) Marketing, Sales and Advertising
ii) Financial markets and services
iii) Banking and Insurance
iv) Industrial Relations & Labor welfare
v) E Commerce

12. Eligibility to Pass: A student requires to obtain 40% Marks in each paper, in theory and practical Examination separately and 45% marks in aggregate to pass the Semester End / Year End Examination.

13.	Evaluation and: Examination	Refer to Ordinance 51(8) of the First Ordinances of Kalinga University.
14.	Eligibility criteria for : ATKT	Refer to Ordinance 51(10) of the First Ordinances of Kalinga University.
15.	General:	In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university, based on the recommendation of the Board of Studies of the subject, shall be final, Provided that a prior approval for the change from Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) shall be necessary. Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.

ORDINANCE 60

Bachelor of Science-Home Science (B.Sc.-Home Science)

1.	Introduction:	Bachelor of Science in Home Science is an undergraduate Home Science professional course. Home Science covers the study of the various sciences that involve nutrition, health and growth including the science that deals with the surroundings and environment. The degree course mainly comprise of the study of the major topics of Home Science like Food Science, Fundamentals of Resource Management. Foundation of Food and Nutrition, etc. In Other words, B.Sc.(Home Science) is a degree course that includes the study of many disciplines such as chemistry, physics, physiology, biology, hygiene, economics, rural development, child development, sociology and family relations, community living, art, food, nutrition, clothing, textiles and home management. The duration of the course is three years and the syllabus for the course is divided into six semesters.
2.	Title:	Bachelor of Science-Home Science (B.Sc.-Home Science)
3.	Faculty:	Faculty of Science.
4.	Duration:	Three years (Six Semester)
5.	Eligibility:	10+2 Passed
6.	Seats:	The basic unit will be that of 60 seats. Multiple of this unit can also be set up.
7.	Admission Procedure:	As Specified in the Ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed.
8.	Academic Year:	The academic session will start in July every year and will continue till June next.
9.	Selection Procedure:	The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every academic cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark Sheets or 10+ 2 passing certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected on any one of the following ground:

1. The fee is not paid.
2. The application form is not signed by candidate and his or her parent / guardian, wherever required.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11. Course structure: There shall be 6 Theory Papers in 1st semester, 6 in 2nd semester, 6 in 3rd semester, 6 in 4th semester, 7 in 5th semester and 7 in 6th semester, each carrying a total of 100 marks which will be divided into two parts – one part of 70 marks based on examination work and 2nd part of 30 marks based on internal assessment. In addition, there shall be four lab work/practical work in 1st semester to 4th semester, each carrying 50 marks divided into two parts – one part of 30 marks on examination work and 2nd part of 20 marks on internal assessment. There shall be six lab work/practical work in 5th semester and 6th semester, each carrying 50 marks divided into two parts – one part of 30 marks on examination work and 2nd part of 20 marks on internal assessment

12. Eligibility to Pass: A student requires to obtain 40% Marks in each paper, in theory and practical Examination separately and 45% marks in aggregate to pass the Semester End / Year End Examination.

13. Evaluation and: Examination Refer to Ordinance 51(8) of the First Ordinances of Kalinga University.

14. Eligibility criteria: for ATKT Refer to Ordinance 51(10) of the First Ordinances of Kalinga University.

15. General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university, based on the recommendation of the Board of Studies of the subject, shall be final, Provided that a prior approval for the change from Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) shall be necessary. Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.

ORDINANCE 61

Master of Computer Science (M.Sc. Computer Science)

1. Introduction: Computer Science today is recognized as a frontier area of knowledge and also a critical enabling tool for assimilating and processing all other spheres of knowledge. It is also recognized the world over that Computer Science is going to change every facet of human existence and will usher in knowledge based society. It is estimated that in India there wil be demand of over 45 lakh computer professionals and with the availability of present educational facilities, the short fall can be in the range of over 25 lakh. Therefore there is a need to take up Computer science education programmes in a big way. This course will equip the students with advanced knowledge in computer field. Such students with specialized knowledge are in good demand and unorganized sector industry and educational institutions.

2.	Title:	Maser of Computer Science (M.Sc. CS)
3.	Faculty:	Faculty of Information Technology
4.	Duration:	Two years (Four semesters)
5.	Eligibility:	Graduation in relevant or allied subject.
6.	Seats:	The basic unit will be of 30 seats. Multiple units can be set up by the board of Management of the University.
7.	Admission Procedure:	As Specified in the Ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed.
8.	Academic Year:	The academic session will start in July every year and will continue till June next.
9.	Selection Procedure:	The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media before the start of every academic cycle.

The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the university.

The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark Sheets or Degree passing certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected on any one of the following ground:

1. The fee is not paid.

2. The application form is not signed by candidate and his or her parent / guardian, wherever required.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

10.	Fees:	The Course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11.	Course structure	There shall be 4 Theory Papers in 1st semester, 4 in 2nd semester, 4 in 3rd semester and 1 project in 4th semester, carrying a total of 100 marks each which will be divided into two parts – one part of 70 marks based on examination work and 2nd part of 30 marks based on internal assessment. In 4th semester project carrying total of 500 marks will be divided into two parts – one part of 300 marks based on examination work and 2nd part of 200 marks based on internal assessment. There shall be one lab work/practical work in 1st & 2nd semester and two lab work/ practical work in 3rd semester, each carrying 50 marks divided into two parts – one part of 30 marks on examination work and 2nd part of 20 marks on internal assessment.
12.	Eligibility to Pass:	A student requires obtaining 40% Marks in each paper, in theory and practical Examination separately and 45% marks in aggregate to pass the Semester End / Year End Examination.

13. Evaluation and: Examination — Refer to Ordinance 51(8) of the First Ordinances of Kalinga University.

14. Eligibility criteria for : ATKT — Refer to Ordinance 51(10) of the First Ordinances of Kalinga for University.

15. General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university, based on the recommendation of the Board of Studies of the subject, shall be final, Provided that a prior approval for the change from Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) shall be necessary. Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.

ORDINANCE 62

Master of Science in Information Technology (M. Sc. IT)

1. Introduction: Information technology pertains to the study, design, and development of computer systems (hardware and software) and networks, which are used for obtaining, processing, and distributing data. This field has been growing at a very fast pace over the last few years, and according to experts, this growth is expected to remain stable. Millions of jobs have been created by IT, and hence, today, it is essential for everyone to understand what information technology is, and how it plays a vital role in every aspect of modern-day life.

   The software applications and the hardware devices are known to be the main elements required for the use of information technology. The web browsers, the operating systems, ERP's and special purpose applications are the software which are used in information technology.

   The applications of the IT sector today, are visible in many different fields, ranging from industrial, managerial, to educational. With newer innovations and developments happening daily, the IT sector is expected to grow at an even faster pace in the coming years, thereby creating ample opportunities for deserving candidates, improving the different processes and procedures, and further enriching our lives.

2. Title: Master of Science in Information Technology (M. Sc. IT)

3. Faculty: Faculty of Information Technology

4. Duration: 2 Years (4 Semesters)

5. Eligibilty: Graduation in relevant or allied subject.

6. Seats: The basic unit will be of 30 seats. Multiple units can also be set up by the Board of Management of the University.

7. Admission Procedure: As Specified in the Ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed.

8. Academic Year: The academic session will start in July every year and will continue till June next.

9. Selection Procedure: The University will issue admission notification in Newspapers, on the Notice Board of the University and in other publicity media like Website, T.V and Radio before the start of every academic cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the Website, on the Notice Board and the selected students will be informed directly about their admission.

The candidates whose result are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark Sheets or Degree Certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which the provisional admission granted will be cancelled.

The admission may be rejected on any one of the following ground:

1. The fee is not paid by the due date.
2. The application form is not signed by candidate and his/ her parents/ guardians.
3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessaary documents and fees.

10. Fees: The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11. Course Structure: There shall be 4 Theory Papers in 1st semester, 4 in 2nd semester, 4 in 3rd semester and 1 project in 4th semester, 1 to 3 semester each carrying a total of 100 marks which will be divided into two parts – one part of 70 marks based on examination work and 2nd part of 30 marks based on internal assessment In addition and 4th semester project carrying total of 500 marks will be divided into two parts – one part of 300 marks based on examination work and 2nd part of 200 marks based on internal assessment, there shall be one lab work/practical work in 1st semester, 2nd semester and two lab work/ practical work in 3rd semester, each carrying 50 marks divided into two parts – one part of 30 marks on examination work and 2nd part of 20 marks on internal assessment.

12. Eligibility to Pass: A student requires to obtain 40% marks in each paper, in theory and practical Examination separately and 45% marks in aggregate to pass the Semester End/Year End Examination.

13. Evaluation and : Examination Refer to Ordinance 51(8) of the First Ordinance of Kalinga University.

14. Eligibility criteria for : ATKT Refer to Ordinance 51(10)of the first Ordinance of Kalinga University.

15. General: In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university, based on the recommendation of the Board of Studies of the subject, shall be final, Provided that a prior approval for the change from Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) shall be necessary. Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.

ORDINANCE 63

Master of Social Work (MSW)

1. Introduction: The Master of Social Work Program is structured to support collaborative work in social work education, research, and public service. Partnerships with more than 300 off-campus social service agencies offer students opportunities to apply their knowledge and skills.

The MSW Program strives to:

- Provide the most current knowledge and skills drawn from various disciplines

- Build students' awareness of professional ethical responsibilities
- Strengthen social work practice through creative and responsive programming, research, and services
- Use instructional and practice relevant technology
- Advance social work knowledge and theory through research and scholarship
- Use instructional and practice relevant technology;
- Develop and nurturing reciprocal relationships with professionals, groups, organizations, and communities
- Work collaboratively within a social and professional context
- Develop and nurturing an appreciation for diversity and the elimination of discrimination.

2. Title: Master of Social Work (MSW)

3. Faculty: Faculty of Arts and Humanities.

4. Duration: 2 Years (4 semesters)

5. Eligibility: Graduation.

6. Seats: The basic unit will be of 30 seats. Multiple units can also be set up by the Board of Management of the university.

7. Admission Procedure: As Specified in the Ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed.

8. Academic Year: The academic session will start in July every year and will continue till June next.

9. Selection Procedure: The University will issue admission notification in Newspapers, On the Notice Board of the University and in other publicity media like websites, TV and radio before the start of every academic cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on Websites, on the Notice Board and the selected students will be informed directly about their admission.

The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree Certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which the provisional admission will be cancelled.

The admission may be rejected on any one of the following ground:

1. The fee is not paid by the due date.

2. The application form is not signed by candidate and his/her parents/ guardians.

3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the students by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

10. Fees: The course fees will be as decided by the Board of Management From time to time with the prior approval of CGPURC.

11. Course Structure: The course shall be conducted in Four Semesters, each having 500 (Five Hundred) marks, totaling to 2000 marks, with 5 papers in each semester each carrying a total of 100 marks which will be divided into two parts – one part of 80 marks based on examination work and 2nd part of 20 marks based on internal assessment. There

shall also be a practicum of 100 marks in 2nd Semester and Research project in 4th Semester. Practicum in social work education is the integral part of social work curriculum which aims to develop the social work learner in themes of knowledge, attitude and skills necessary for effective social work practice. This includes various activities Viz, orientation visits, concurrent field work visits, field work seminar, (issue based seminar/ based on community skills) Individual conference, group conference, tribal/ rural camp, study tour and viva-voce

12.	Eligibility to Pass:	A student requires to obtain 40% marks in each paper, in theory and practical Examination separately and 45% marks in aggregate to pass the Semester End Examination. 50% passing in social work practicum is compulsory so as to promote the learner in next semester.
13.	Evaluation and: Examination	Refer to Ordinance 51(8) of the First Ordinance of Kalinga University.
14.	Eligibility criteria for : ATKT	Refer to Ordinance 51(10)of the first Ordinance of Kalinga University.
15.	General:	In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university, based on the recommendation of the Board of Studies of the subject, shall be final, Provided that a prior approval for the change from Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) shall be necessary. Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

संशोधित

क्रमांक/47/भू-अर्जन/प्र.क्र. 12/अ-82/14-15.—छ.ग. राजपत्र दिनांक 17 अप्रैल 2015 के पृष्ठ क्रमांक-539 में भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 11 के अन्तर्गत ग्राम-गुदगुदा, प.ह.नं. 56, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर में समोदा बैराज परियोजना के निर्माण में डूबान में आई भूमि का अर्जन हेतु अधिसूचना प्रकाशित हुआ है. उक्त अधिसूचना में खसरा नम्बर 429/3 का रकबा 0.04 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 429/2, टंकन त्रुटिवश अंकित हो गया है. जिसे राजपत्र में खसरा नम्बर 429/3 का रकबा 0.04 हेक्टेयर पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

संशोधित

क्रमांक/48/भू-अर्जन/प्र.क्र. 6/अ-82/14-15.—छ.ग. राजपत्र दिनांक 24 अप्रैल 2015 के पृष्ठ क्रमांक-565 से 571 तक में भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 11 के अन्तर्गत ग्राम-चपरीद, प.ह.नं. 51, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर में समोदा बैराज परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु अधिसूचना प्रकाशित हुआ है. उक्त अधिसूचना में खसरा नम्बर 1286/3 का रकबा 0.02 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 1286/2, टंकन त्रुटिवश अंकित हो गया है. जिसे राजपत्र में खसरा नम्बर 1286/3 का रकबा 0.02 हेक्टेयर पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक/03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-बहेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1208	0.024
योग	1	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरहोली जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक/04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	628	0.01
योग	1	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी भिंभौरी जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक/05/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-कोहड़िया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.51
1/3	0.60

	(1)	(2)
	1/4	0.88
	1/5	0.77
योग	4	2.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोर नाला डायवर्सन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 21 जनवरी 2016

क्रमांक/20/क/भू-अर्जन/12/अ-82/2014-15—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-सानटेमरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.36 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	253	0.22
	259	0.32
	254	0.01
	255	0.18
	256	0.10
	245	0.20
	249	0.05
	246	0.28
योग	8	1.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 21 जनवरी 2016

क्रमांक/22/क/भू-अर्जन/14/अ-82/2014-15—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-छातामौहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.65 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
335	0.12
336/2	0.03
336/1	0.68
35	0.02
323	0.52
316/1	0.21
2/18	0.08
316/3	0.13
315/1	0.08
298	0.10
22/3	0.09

(1)	(2)
4/2	0.01
316/4	0.14
331	0.01
315/2	0.14
313/1	0.13
313/2	0.01
300	0.12
295/1	0.14
297/01	0.25
295/3	0.05
295/2	0.12
285/1	0.09
285/2	0.50
284	0.02
32	0.06
43	0.56
44	0.13
40	0.07
39/1	0.27
56	0.13
59/1	0.19
57	0.34
12	0.12
63	0.01
59/2	0.25
60/2	0.05
60/1	0.08
14	0.81
105	0.03
13	0.06
10/3	0.04
11/1	0.03
10/4	0.04
11/2	0.03
10/1	0.05
11/3	0.04
26/1	0.03
10/2	0.05
28	0.04
11/4	0.04
2/5	0.12
33	0.01
4/1	0.03
7/1	0.12
16/1	0.11
5	0.30
64	0.15
19	0.08
23	0.23
34	0.16
योग 61	8.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 21 जनवरी 2016

क्रमांक/24/क/भू-अर्जन/15/अ-82/2014-15—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-लोहरिनडोंगरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/1	0.02
2/2	0.06
2/3	0.04
9	0.01
6/2	0.05
2/4	0.03
6/3	0.40
6/20	0.10
6/4	0.11
5/2	0.05
6/17	0.01

	(1)	(2)
	6/5	0.11
	6/19	0.05
	16	0.40
	13	0.16
	286/13	0.10
	286/29	0.11
	286/27	0.11
	6/18	0.01
	286/28	0.18
	286/26	0.10
	286/25	0.21
योग	22	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्रमांक 688/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-साजाबहरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	51	0.40
	123/2, 124	0.06
योग	3	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चैतमा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 नवम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-बड़गांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/2	0.105

	(1)	(2)
	31/4	0.024
योग	2	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के तहत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2016

क्र./43/वा./भू.अ./प्र.क्र./04/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसुलीडीह, प.ह.नं. 7/8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.340 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	331	0.210
	332	0.130
	333	0.050
	334	0.020
	335	0.020
	354	0.120
	336	0.030
	359	0.090
	337	0.080
	338	0.140
	339	0.130
	360	0.200
	358	0.380
	353	0.530
	352	0.210
योग	15	2.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-परसुलीडीह एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-माड़ाकोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-42.34 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
351/1	1.50
156	1.07
151/1	0.67
77	0.16
313	0.04
359	0.15
363	0.48
364/1	2.54
169	0.70
174	0.34
314	0.03
325	0.53
328	0.50
329	0.14
332	1.83
319	0.05
334	0.60
157/1	0.50
157/2	0.22
157/3	1.18
349	0.56
58/9/2	0.19
324/1	0.08
159/1	0.69
159/2	0.06
353	0.56
364/2	0.40
365	0.16
351/2	0.40
352	0.04
307	0.10
323	0.57
333	0.74
361	0.68
362	0.10
355	1.48
360	0.42
350/3	0.07
366/2	1.55
350/4	0.06
351/3	0.18
304/2	0.12
304/3	0.06
315	0.12
326	0.10
330	0.07
198/2	0.02
159/3	0.18
159/4	0.20
160	0.13
163/2	0.08
173	0.34
327	0.19
324/2	0.07
151/2	0.20
153/1	1.44
155	0.88
175	0.94
335	2.90
350/1	2.56
344	1.51
345	2.00
346	0.35
347	0.18
348	0.99
308	0.38
350/2	0.07
82	0.10
154	0.32
171	0.13
177	0.20
151/3	0.67
152	0.18
153/2	0.48
331	0.08
161	0.35
159/5	0.50
79	0.08
78/1	0.32
83	0.13
78/2/1	0.24
78/5	0.16
योग	42.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जशपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्रमांक/412/वित्त स्था./स्थानीय अवकाश/2016.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4/भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं हिम शिखर गुप्ता, कलेक्टर जशपुर वर्ष 2016 के लिये जशपुर जिले में निम्नलिखित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्रमांक	स्थानीय अवकाश का नाम	दिनांक	दिन	रिमार्क
1	होली का दूसरा दिन	24-03-2016	गुरुवार	जशपुर जिले में
2	अनंत चतुर्दशी	15-09-2016	गुरुवार	जशपुर जिले में
3	दीपावली का दूसरा दिन	31-10-2016	सोमवार	जशपुर जिले में

हिम शिखर गुप्ता,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

बेमेतरा, दिनांक 21 जनवरी 2016

क्रमांक/8226विलिप्र/2016.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रीता शांडिल्य, कलेक्टर बेमेतरा वर्ष 2016 हेतु बेमेतरा जिला में स्थित समस्त सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं के लिये निम्नलिखित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं :—

क्र.	स्थानीय अवकाश का नाम	दिनांक	दिन
1	गणेश चतुर्थी	05 सितम्बर 2016	सोमवार
2	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या	30 सितम्बर 2016	शुक्रवार
3	दीपावली का दूसरा दिन	31 अक्टूबर 2016	सोमवार

रीता शांडिल्य,
कलेक्टर.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्रमांक/1223/न.ग्रा.नि./चंद्रपुर/शोध./2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट चंद्रपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973)

की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

चंद्रपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मड़वा, सिरौली एवं बिरहाभाठा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बिरहाभाठा, पलसदा, बिलाईगढ़, चंदेली, महादेवपाली, कलमा एवं बालपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बालपुर, कलमा, महादेवपाली, चंद्रपुर एवं काशीडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम काशीडीह, मिरौनी एवं मड़वा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, चंद्रपुर जांजगीर (छ.ग.)

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

क्रमांक 1377/नग्रानि/2015.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15(3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट भखारा निवेश क्षेत्र में की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं. इस सूचना की प्रतिलिपि उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

भखारा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सिलघट, सुपेला, सेमरा, सिंगदेही, जोरातराई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कुर्रा, खपरी, कोलियारी, जोरातराई ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम गातापार, कोसमर्रा, सिहाद, कुर्रा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सिलघट, गाड़ाडीह, रामपुर, बोरझरा, गातापार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, भखारा एवं कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी (छ.ग.)

No. 1377/T&CP/2015.—It is published for general information to the Public that in Persuance of subsection (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) an existing land use map register of the Planning Area of "Bhakhara" as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Commissinor Director, Town and Country Planning C.G. Copy of this notice is being sent for publication in the "Chhattisgarh Gazette" under sub section (4) of section 15 of the said Act and will be conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limites of Bhakhara Planning Area

NORTH : Northern limits of Villages Silghat, Supela, Semra, Singdehi, Joratarai.
EAST : Eastern limits of Villages Kurra, Khapri, Koliyari, Joratara.
SOUTH : Southern limits of Villages Gatapar, Kosmarra, Sihad, Kurra.
WEST : Western limits of Villages Silghat, Gadadih, Rampur, Borjhara, Gatapar.

The said adopted map shall be open for inspection at the following place with effect from the date of publication for a period of 15 days during office hours except holidays.

Inspection Place : Office of the Nagar Panchayat Bhakhara And Assistant Director Town and Country Planning, Dhamtari (C.G.)

आर. के. मालवीया,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd January 2016

No. 522/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Mahesh Babu Sahu, J.M.F.C., Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon
2.	Shri Nixion Daved Lakra, J.M.F.C., Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon
3.	Ms. Shubhda Goyal, J.M.F.C., Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon

बिलासपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

क्रमांक 548/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद्द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, मरवाही की पेण्ड्रारोड में श्रृंखला न्यायालय की बैठक एक सप्ताह से बढ़ाकर दो सप्ताह की जाती है.

No. 548/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby increase the sittings of Link Court of Civil Judge Class-II, Marwahi at Pendra-Road to two weeks every month instead of one week.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 27th January 2016

No. 1/L.G./2016/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 04 days from 14-12-2015 to 17-12-2015 along with permission to leave headquarters from 13-12-2015 to 17-12-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 173 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th January 2016

No. 2/L.G./2016/II-3-26/2014.—Shri Sirajuddin Qureshi, Special Judge (Atrocities), Bastar at Jagdalpur is hereby, granted earned leave for 02 days from 26-12-2015 to 27-12-2015 suffixing winter vacation along with permission to leave headquarters from 26-12-2015 to 31-12-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 146 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th January 2016

No. 3/L.G./2016/II-2-4/2005.—Shri Manish Kumar Naidu, Special Judge (Atrocities), Raigarh is hereby, granted earned leave for 03 days from 26-12-2015 to 28-12-2015 suffixing winter vacation along with permission to leave headquarters from 26-12-2015 to 31-12-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Naidu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 279 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th January 2016

No. 4/L.G./2016/II-3-4/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted commuted leave for 05 days from 14-12-2015 to 18-12-2015.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 395 days of half-pay leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th January 2016

No. 5/L.G./2016/II-2-24/2015.—Shri Venseslas Toppo, Officer-On-Special Duty, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 22-12-2015 to 26-12-2015 along with permission to leave headquarters from 22-12-2015 to 27-12-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Toppo, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 59 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th January 2016

No. 6/L.G./2016/II-3-40/2007.—Shri Arvind Kumar Verma, Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 06 days from 28-12-2015 to 02-01-2016 along with permission to leave headquarters from the evening of 26-12-2015 till the evening of 03-01-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Verma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 292 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th January 2016

No. 7/L.G./2016/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, Judge, Family Court, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 11 days from 23-12-2015 to 02-01-2016 along with permission to leave headquarters from 23-12-2015 to 02-01-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 274 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th January 2016

No. 8/L.G./2016/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondaley, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted earned leave for 03 days from 31-12-2015 to 02-01-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Godaley, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 196 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 27th January 2016

No. 9/L.G./2016/II-3-35/2011.—Shri Abdul Zahid Qureshi, Special Judge (Atrocities), Raipur is hereby, granted earned leave for 02 days on 26-12-2015 & 27-12-2015 suffixing winter vacation along with permission to leave headquarters from 24-12-2015 to 30-12-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 242 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th January 2016

No. 10/L.G./2016/II-03-07/2015.—Shri Santosh Sharma, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 02 days on 26-12-2015 & 27-12-2015 suffixing winter vacation along with permission to leave headquarters after the Court hours of 24-12-2015 till before the Court hours of 31-12-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 163 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th January 2016

No. 11/L.G./2016/II-2-12/2009.—Shri Ashok Kumar Goyal, Judge, Family Court, Jashpur is hereby, granted earned leave for 10 days from 30-11-2015 to 09-12-2015 and permission to prefix holiday of 29-11-2015 along with permission to leave headquarters and earned leave for 03 days from 31-12-2015 to 02-01-2016 in continuation of winter vacation along with permisison to leave headquarters from 27-12-2015 to 03-01-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Goyal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th January 2016

No. 13/L.G./2016/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, Registrar (Computerization)-cum-Central Project Co-ordinator, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 06 days from 26-12-2015 to 31-12-2015 along with permission to leave headquarters from the morning of 25-12-2015 till the morning of 02-01-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 246 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th January 2016

No. 14/L.G./2016/II-2-16/2015.—Smt. Suman Ekka, Judge, Family Court, Korba is hereby, granted earned leave for 02 days on 14-12-2015 & 15-12-2015 along with permission to leave headquarters from 06.30 p.m. of 12-12-2015 till before the working hours of 16-12-2015 and earned leave for 02 days on 26-12-2015 & 27-12-2015 suffixing winter vacation along with permission to leave headquarters from 25-12-2015 till before the Court hours of 30-12-2015.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 28th January 2016

No. 15/L.G./2016/II-2-07/2009.—Shri Mahadev Katulkar, Judge, Family Court, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 05 days from 05-10-2015 to 09-10-2015 along with permission to leave headquarters from 04-10-2015 to 11-10-2015, earned leave for 02 days from 19-11-2015 to 20-11-2015 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 18-11-2015 till before the Court hours of 23-11-2015 and earned leave for 06 days from 18-12-2015 to 23-12-2015 along with permission to leave headquarters from 18-12-2015 till before the Court hours of 26-12-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katulkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 292 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th January 2016

No. 16/L.G./2016/II-3-35/2008.—Shri Sypriel Xess, II Additional Principal Judge, Famiy Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 06 days from 21-12-2015 to 26-12-2015 along with permission to leave headquarters from 19-12-2015 to 27-12-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Xess, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th January 2016

No. 17/L.G./2016/II-2-5/2006.—Shri Ravishankar Sharma, Registrar (I & E) and I/c S & A Cell, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 12 days from 02-01-2016 to 13-01-2016 along with permission to leave headquarters from 02-01-2016 to 13-01-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 279 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 28th January 2016

No. 18/L.G./2016/II-3-10/2007.—Shri Sharad Kumar Gupta, Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 06 days from 21-12-2015 to 26-12-2015 along with permission to leave headquarters from 19-12-2015 to 27-12-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Gupta, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 256 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).